Pushpa Chauhan
Professor, Deptt of Economics
Vaishali Mahila College, Hajipur

29/05/2020
PART-III, Paper-V

आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका

अर्थव्यवस्था के संचालन में राज्य की निर्णायक भूमिका होती है। राज्य के नियन्त्रण के बिना पूर्वनियोजित आर्थिक विकास सम्भव नहीं है।

प्रारम्भ से ही आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप रहा है। 19 वीं शदी के पूर्वार्द्ध तक यह मान्यता थी कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राजा का मुख्य कार्य बाह्य सुरक्षा तथा आन्तरिक शान्ति व्यवस्था व न्यायिक व्यवस्था को कायम रखना था।

19 वीं शदी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक क्रान्ति, आर्थिक संकट की उपस्थिति एवं आर्थिक विषमताओं के कारण यह प्रश्न उठने लगा कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सभी स्तरों पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। पूंजीवादी समर्थक देश भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करने लगे।

20 वीं शदी तक आते आते राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों में आमूल परिवर्तन आ गया था। समाजवाद का उदय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास तथा 1929 के विश्वव्यापी मंदी ने राज्य को आर्थिक गतिविधियों में विस्तार के लिए प्रेरित किया। नव-स्वतंत्र अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए सरकार की भूमिका बाध्यकारी थी।

अल्पविकसित देशों में राज्य की भूमिका को रेखांकित करते हुए UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन दल ने लिखा है कि "उन सामान्य कार्यों के अतिरिक्त जिन्हें सरकार प्रायः करती है, और कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरकार को इसलिए सम्पन्न करना चाहिए क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं तथा निजी प्रयास

द्वारा या तो उत्पन्न नहीं किए जा सकते या कुशलता से संपादित नहीं किए जा सकते हैं।"

विकासशील देशों में अनेक आर्थिक अवरोध आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध करते हैं। क्योंकि प्रायः इन देशों में पूंजी का अभाव, प्राकृतिक साधन का अल्पदोहन, बचत एवं विनियोग की कमी, औद्योगीकरण का अभाव, बढ़ी बेरोजगारी, निर्धनता के दुश्चक्र के कारण आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं हो पाता है। अतः इन देशों में सरकार का दायित्व होता है कि वह पूंजी, कुशल श्रमिक, उद्यमता, तकनीकी ज्ञान, शक्ति एवं ऊर्जा के साधन उपलब्ध कराए।

राज्य आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा कठोरता को समाप्त कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रो० डब्ल्यू० ए० लेविस ने ठीक ही कहा है कि "बुद्धिमान सरकार की सक्रिय प्रेरणा के बिना किसी भी राष्ट्र ने आर्थिक विकास नहीं किया है।"

अतः अल्पविकसित देशों के तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए सिर्फ सरकारी हस्तक्षेप बल्कि सरकारी उपक्रम के विस्तार करना अत्यन्त आवश्यक है। इन देशों में सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य द्वारा अन्य उपायों जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति एवं श्रम नीति से आर्थिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने में अपना योगदान देती है। इस कारण राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है।

पश्चिमी राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राज्य का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।

इस प्रकार अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास

के लिए राज्य के द्वारा अपनाए गए उपायों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं।

(A) प्रत्यक्ष उपाय (Direct Measures)

(B) अप्रत्यक्ष उपाय (Indirect Measures)

A. प्रत्यक्ष उपाय : इसके अन्तर्गत निम्न उपाय शामिल हैं:-

(i) आर्थिक एवं सामाजिक उपरीपूंजी की व्यवस्था करना - आर्थिक अधः संरचना के अभाव में विकास सम्भव नही है। अल्पविकसित देशों में आर्थिक अधः संरचना का अभाव पाया जाता है। इनके विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। आर्थिक उपरीपूंजी (overhead) में यातायात, परिवहन के साधन, बंदरगाह, संचार व्यवस्था, ऊर्जा के साधन सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित है। इसी तरह सामाजिक उपरीपूंजी (overhead) के निर्माण में भी भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, आवास सुविधा का निर्माण जैसी सामाजिक उपरीपूंजी की आवश्यकता होती है अतः सरकार द्वारा ही इन आर्थिक सामाजिक आवश्यकता को भारी मात्रा में निवेश कर पूरी किया जाता है। यह सरकार की प्रारम्भिक जिम्मेदारी है

(ii) कृषि क्षेत्र का विकास - अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है आज भी ~~...~~ ऐसे राष्ट्र में जनसंख्या का अधिक भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है भारत में आज भी 60% लोग कृषि पर आश्रित है और राष्ट्रीय आय में योगदान 18% के करीब है कि कृषि क्षेत्र आज भी अन्य देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है

क्योंकि जोत का अनार्थिक आकार, उपविभाजन एवं अपखण्डन, प्राचीन तरीकों से खेती करना, साख सुविधा का अभाव, सिंचाई सुविधा का अभाव, उत्तम खाद एवं बीज का अभाव पाया जाता है अतः देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। अतः सरकार द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाकर एवं कृषि विकास के लिए योजनागत व्यय को बढ़ाकर विकसित किया जाता है।

(iii) औद्योगिक विकास - अविकसित देशों में औद्योगीकरण का अभाव होता है। औद्योगिक विकास के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सरकार (राज्य) एक उद्योगपति की तरह प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों की स्थापना करती है। मूलभूत उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाता है, इन उद्योगों में राज्य की प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक वस्तुओं की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उद्योगों में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना है। भारत, जर्मनी, जापान आदि देशों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकारों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है।

राज्य अप्रत्यक्ष रूप से निजी उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान कर औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करती है। राज्य के द्वारा कर में छूट प्रदान कर, मशीन एवं तकनीकी का आयात कर, आवश्यक वित्त उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करती है।

(iv) साधनों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करना - अल्पविकसित देशों में उत्पादन के साधनों का उचित विदोहन नहीं होने के कारण साधनों का अपव्यय होता है जिससे विकास की गति धीमी रहती है। इन देशों में भूमि साधनों का प्रयोग

Contd.

Scanned with CamScanner